भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5033

दिनांक 31 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर योजना की सामाजिक संपरीक्षा

5033. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन स्टॉप सेंटर योजना के प्रारंभ से अब तक इसके लिए आबंटित, संवितरित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत एक वर्ष के दौरान भारत और विदेशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत विशेषीकृत सहायता प्रदान करने वाले चिकित्सकों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या विगत दो वर्षों में इस योजना की सामाजिक संपरीक्षा हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): अब तक सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 801 वन स्टॉप केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 733 ओएससी कार्यशील हैं। इसके शुरुआत के बाद से, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिलों को कुल 735.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जिसमें से आज तक कुल 327.50 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

इसके अलावा, निर्भया फंड के ढांचे के तहत गठित अधिकार प्राप्त समिति ने प्रवासी भारतीयों के महत्वपूर्ण अनुपात वाले देशों में भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए विदेशों में 9 भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) में ओएससी जैसी सुविधाओं की स्थापना के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है।

(ग) : सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के माध्यम से ओएससी के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करती है। हाल ही में सरकार ने 'स्त्री मनोरक्षा' नामक प्रोजेक्ट के तहत हिंसा और संकट का सामना कर रही महिलाओं की मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की सेवाएं ली हैं।

(घ) : नीति आयोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वन स्टॉप सेंटर(ओएससी) स्कीम सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया गया। अध्ययन ने स्कीम की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया। थर्ड पार्टी के मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर, वन स्टॉप सेंटर स्कीम को 15वें वित्त आयोग चक्र की 2025-26 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति के तहत उप-स्कीम 'संबल' के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है और इसे महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर मुख्य आधार के रूप में नामित किया गया है।

****